बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-815
23/11/2026

899 राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल माध्यम से मामलों की होगी सुनवाई, कोर्ट जाने से लोगों को मिलेगी राहत :– सम्राट

मुख्य बिंदु :–

- राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण।
- समय और संसाधन की होगी बचत, न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ होगा कम तथा सुनवाई की गुणवत्ता और पारदर्शिता में आएगी वृद्धि।
- वर्चुअल सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग एवं ट्रांसक्रिप्शन होगा उपलब्ध, आदेशों की गुणवत्ता की जांच के लिए बनेगा विशेष सेल'।
- एस0एम0एस0 के साथ कॉल सेंटर एवं अन्य वैकल्पिक माध्यमों से भी आम लोगों को दी जाएगी सुनवाई की सूचना।
- वर्चुअल सुनवाई की इस व्यवस्था की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

पटना, 23 नवम्बर 2026 :– मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के अंतर्गत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस व्यवस्था के शुरू होने से अब आम नागरिकों को राजस्व न्यायालयों में होने वाली सुनवाई के लिए बार–बार कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वे डिजिटल माध्यम से अपने मामलों की सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। इससे राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही अधिक सुगम, पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी बनेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधाार विभाग को भी आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। 899 राजस्व न्यायालयों में वर्चुअल माध्यम से मामलों की सुनवाई होगी। राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था शुरू होने से आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी

तथा राजस्व न्यायालय जाने से राहत मिलेगी। बिहार में राजस्व से जुड़े करोड़ों आवेदन एवं मामले लंबित रहते हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने से मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। यह पहल सरकार के सात निश्चय–3 के अंतर्गत 'सबका सम्मान–जीवन आसान' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था से आम लोगों के समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। उन्हें सुनवाई के लिए दूर–दराज से राजस्व न्यायालयों तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे विशेष रूप से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें सुलभ तरीके से न्याय मिल सकेगा। इस प्रणाली के माध्यम से सुनवाई की पूरी रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्शन उपलब्ध रहेगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी तथा सुनवाई की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि पारित आदेशों की स्क्रूटिनी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि आदेशों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बेहतर हो सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्चुअल सुनवाई की इस व्यवस्था की व्यापक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने आदेशों की गुणवत्ता की नियमित जांच के लिए एक विशेष सेल गठित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनवाई से संबंधित सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से भेजने के साथ–साथ इसके लिए अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए कॉल सेंटर के माध्यम से भी संबंधित पक्षकारों को सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई की तिथि एवं समय की जानकारी मिलने में कठिनाई न हो। यह पहल डिजिटल बिहार के निर्माण और आधुनिक, जवाबदेह एवं पारदर्शी राजस्व व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम के दौरान राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित एक वीडियो फिल्म दिखाई गई साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने इससे संबंधित एक प्रस्तुतीकरण भी दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अब वादों की ऑनलाइन सुनवाई के साथ–साथ डिजिटल माध्यम से साक्ष्य एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पक्षकार अपने मामलों की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे सुनवाई एवं मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया अधिक सरल, सुगम और पारदर्शी बनेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव श्री अमित कुमार पाण्डेय, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक श्री सुहर्ष भगत सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी एवं राजस्व न्यायालय से संबंधित पदाधिकारी जुड़े हुये थे।

******